(ग) सरकार ने कीमतों को नियंत्रित करने संबंधी पहले से ही अनेक उपाय किये हैं। इनमें अनिवार्य पूंजीगत माल को मुक्त सामान्य लाइसेंस से लाइसेंस की श्रेणी में परिवर्तित करना, चुने हुए क्षेत्रों की आवश्यकता के लिए कच्ची सामग्रियों और संघटकों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने में छूट देना, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का कठोरता से पालन करना और आयात संबंधी आवश्यकताओं आदि को पूरा करने के लिए आर.ई.पी. लाइसेंस के उपयोग पर अधिकाधिक बल देना शामिल है।

गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के कचरे का प्रसंस्करण

2676. **श्री राम अवधेश सिंह : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रतिवर्ष इस्पात का कितना उत्पादन होता है और वहां कितना मशिया कचरा बचता है भिलाई इस्पात संयंत्र के स्क्रैप और सप्लाई विभाग तथा फेरो स्क्रैप निगम द्वारा कितने टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है जो इस तरह का काम करती है ;

(ख) गैर-सरकारी एजेंसियां द्वारा कितने टन कचरे का प्रसंस्करण किया जाता है ;

(ग) इस्पात गलन शाप में तथा फेरो स्क्रैप निगम द्वारा प्रसंस्कृत कचरे से किए गए इस्पात के उत्पादन की प्रति टन लागत कितनी है और इस प्रकार उत्पादित इस्पात किस दर पर बेचा जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने सभी इस्पात संयंत्रों को निदेश जारी किये थे कि या तो वे स्वयं इस पूरे कचरे का प्रसंस्करण करें या इसे फेरो जैसे निगम से करायें, यदि हां, तो इन निदेशों का पालन न किए जाने के लिए भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर इस्पात संयंत्र के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय की अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) भिलाई इस्पात कारखाने में वर्ष 1989-90 के दौरान इस्पात का कुल उत्पादन 32.5 लाख मी. टन था । कुल 8.13 लाख मी. टन स्क्रैप उपभोग किया गया और इस आवश्यकता की पूर्ति निम्नलिखित स्रोतों से की गयी थी :—

	लाख मी. टन	प्रतिशतता
1. भिलाई इस्पात कारखाना माल पुनर्प्राप्ति विभाग	4.95	60.9
2. फेरो स्क्रैप निगम लि.	2.51	30.8
3. प्राइवेट एजेंसियां (मेसर्स एम. पी. बिल्डर्स, भिलाई)	0.39	4.77
4. सहायक इस्पात कारखानों से प्रतों आपूर्तियां	0.28	3.52

(ख) प्राइवेट एजेंसियों द्वारा 0.39 लाख मी. टन स्क्रैप प्राप्त किया गया।

(ग) इस्पात तैयार करने में एकत्रित इस्पात कारखाने द्वारा प्रयुक्त विद्यमान प्रौद्योगिकी इस्पात गलन शाला में कुल प्रभार में स्क्रैप की बहुत कम मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी से केवल स्क्रैम से ही इस्पात का उत्पादन नहीं हो सकता। अतएव, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड द्वारा संसाधित स्क्रैप से इस्पात का उत्पादन लागत का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां। सेल ने अपने नियंत्रणाधीन सभी कारखानों को निजी सुविधाओं अथवा सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों की मार्फत सम्पूर्ण स्क्रैप की प्राप्ति

तथा संशोधित करने के निदेश जारी किया था।

इन निदेशों को प्रतिक्रिया स्वरूप सेल के कारखानें साधारणतः अपने निज सुविधाओं तथा फैरो स्क्रैप निगम लि० मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि० और हिन्दुस्तान टार्च बर्नर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जैसी अन्य सरकारी क्षेत्र की एजन्सियों के मार्फत इस्पात तथा लोहे स्क्रैप दोनों का इष्टतम प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं। तथापि, सरकारी क्षेत्र की एजेन्सियों द्वारा प्रदाताओं का सम्पूर्ण और पूरी तरह संभाल कार्य अभी नहीं किया गया है। धमन भट्टी के धातुमल के ढेरों के मामले में, लोहे की कम प्राप्ति के लिए किए सरकार क्षेत्र के अभिकरण ने रुचि नहीं दिखाई है। सेल ने फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड से स्क्रैप की प्राप्ति के सम्पूर्ण कार्य का अधिग्रहण करने के लिए कहा है, उसे अभी तक उत्तर नहीं मिला है।

Recovering of export incentives earned by companies to meet the loss interms of foreign exchange

2677. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry have decided to recover the export incentives earned by the companies on export of drugs at a value loss in terms of foreign exchange;

(b) what are the names of companies involved and what were their exports during the last three years, yearwise along with the names of the products involving value loss;

(c) what was the quantity of each drug exported during last three years, yearwise, country to which exported and the FOB value of exports; yearwise;

(d) whether it is also a fact that same material of bulk drugs and intermediates were re-imported for meeting the exports orders of end products and

(e) what steps have been taken to verify and check such activities which are against the national interest?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) to (e) Some cases of negative value addition have lately come to notice. The matter is under examination.

Cut in foreign aid

2678. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether India is likely to get less foreign aid during 1990-91 than that received last year;

(b) if so, whether this was made known by the World Bank's Vice President;

(c) what are the main reasons therefor; and

(d) what is the actual amount of aid India will now get?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) to (d) The indications of probable aid levels pointed to commitments level of U.S. $ 6.0—6.5 billion for 1990-91. This did not include pledges of one donor country, which was to be announced later. In 1989-90, an indicative commitment level of U.S. $ 6.7 billion was announced. On comparable basis, the aid indication this year are of the same level as last year.

Import of Almonds

2679. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have liberalised the import of almonds;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what are the names of the importing firms in the country?